



56.

ग्रंथ - 855-PBR-16

०५१४०८६ राजस्व मुद्रा संचालन उपायिका (मो. ५०)

५०का/

1 निगरानी / 2016

मुकेश माई प्रबोध
हत्ता आज ११३ : १६

प्रकाश

११३ : १६
शास्त्रीय नाम निवासियर

मुकेश माई
११३ : १६ प्रबोध
प्रबोध

वर्तना विहित पात्र ५/८
मो. शम्भवन विहित निवासि
प्रितरगां - आवेदन
वर्तमान

०५१४०८६ के ५/८ के मुद्रा विहित
जाते विद्यार निवासि
प्रितरगां निवासि
(मो. ५०)

प्राथमिक प्रबोध उपायिका ०५१४०८६ के ५/८ के मुद्रा विहित
मित्र ५०का/ २१/१४-१३/१६ आवेदन १४-१२-२०१५ ०५१४०८६
लकड़ी लजाए मुद्रोद्धर - प्रितरगां निवासि उपायिका के ५/८
माननीय मुद्रोद्धर जी

प्राथमिक आवेदन की निवासी निवासि निवासि निवासि निवासि
आवासीय निवासि निवासि निवासि निवासि निवासि
निवासि निवासि निवासि निवासि निवासि निवासि
निवासि के उपर्युक्त निवासि

०५१४०८६

खाली

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 855-पीबीआर/2016

जिला ग्वालियर

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	जिला ग्वालियर पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-7-18	<p>उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।</p> <p>2- आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसीलदार भितरवार जिला ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 21/अ-6/2014-15 में पारित आदेश दि. 14-12-2015 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।</p> <p>3- आवेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो प्रकरण की परिस्थितियों को समझा एवं गुणदोषपर बिना विचार किये आवेदक का साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर समाप्त किये जाने का आदेश दिया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी कहा गया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया जाना न्याय दान के लिये अति आवश्यक है, क्योंकि बिना साक्ष्य एवं सुनवाई के न्याय प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती। उनके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश निरस्त कर साक्ष्य का अवसर दिये जाने का निवेदन किया।</p> <p>4- अनावेदकपक्ष अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यही कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश विधिवत होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये।</p> <p>5- उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने के कई अवसर देने के बाद ही साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त किया गया है। आवेदक ने दस्तावेजी साक्ष्य पहले ही पेश कर चुके हैं और क्या साक्ष्य पेश करना चाहते हैं यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः तहसील न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।</p> <p>6- उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार भितरवार जिला ग्वालियर द्वारा पारित अंतरिम आदेश दि. 14-12-2015 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।</p>	 